भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2831

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

पश्चिम बंगाल में कोयला ब्लॉक को प्रचालनशील करना

2831. श्री जगन्नाथ सरकारः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा देउचा पचामी कोयला ब्लॉक के प्रचालन में देरी से राज्य की ऊर्जा और आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश की कोयला आवश्यकताओं को पूरा करने की बड़ी क्षमता होने के बावजूद देउचा पचामी कोयला ब्लॉक के प्रचालनशील न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार को उक्त परियोजना में तेजी लाने के लिए कोई सहायता या दिशानिर्देश दिए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देउचा पचामी कोयला ब्लॉक के प्रचालन से आर्थिक और रोजगार संबंधी क्या लाभ होने का अनुमान है; और

(ड.) केंद्र सरकार द्वारा इस राष्ट्रीय संपत्ति का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी हितधारकों की संभावित भागीदारी सहित किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): पश्चिम बंगाल में स्थित देउचा पचामी कोयला ब्लॉक के प्रचालनरत होने की निर्धारित तिथि 27.09.2027 है। फिलहाल इस ब्लॉक के प्रचालनरत होने में कोई विलंब नहीं हुआ है।

(ग): जी, हां। निर्धारित समय पर कोयला ब्लॉकों के विकास के लिए, सभी हितधारकों की उपस्थिति में बैठकों के माध्यम से नियमित आधार पर प्रगति की निगरानी की जा रही है।

इसके अलावा, कोयला ब्लॉकों के समय पर विकास के लिए कोयला ब्लॉक आवंटितियों की सहायता हेतु मंत्रालय द्वारा एक परियोजना प्रबंधन इकाई भी नियुक्त की गई है।

(घ): एक बार पूर्ण रूप से प्रचालनरत हो जाने पर इस कोयला ब्लॉक में लगभग 1 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने तथा आर्थिक गुणक प्रभाव के माध्यम से न केवल जिले या इसके आसपास के क्षेत्रों बल्कि पूरे क्षेत्र में आर्थिक परिवर्तन लाने की क्षमता है।

(ङ.): पश्चिम बंगाल राज्य की बढ़ती ऊर्जा माँगों को पूरा करने के लिए निर्धारित समय में विकास और अपने कैप्टिव विद्युत संयंत्रों में कोयले के उपयोग हेतु कोयला मंत्रालय द्वारा डब्ल्यूबीपीडीसीएल को यह कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया है। निर्धारित समय-सीमा के अनुसार कोयला ब्लॉकों के विकास हेतु, सभी हितधारकों की उपस्थिति में बैठकों के माध्यम से नियमित आधार पर प्रगति की निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, कोयला ब्लॉक आवंटितियों की सहायता के लिए मंत्रालय द्वारा एक परियोजना प्रबंधन इकाई भी नियुक्त की गई है जो परियोजना प्रस्तावक का प्रत्येक चरण में मार्गदर्शन करती है।

****